महोदय से यह कहना चाहता हूं कि हुबली धारवाड़ एयरपोर्ट एक ज़माने से हवाई जहाज़ के स्वागत के लिए दुल्हन जैसा सजधज गया है। इस संबंध में मुझे मीरां का एक भजन याद आता है—

आवन कह गये, आप न आवे,
बाण पड़ी ललचावन की,
यह दो नयना कहा नहीं मानें,
नदियां बहे जैसे सावन की।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि गैर सरकारी विमान भारत के मुक्त गगन में उड़ने के लिए मुक्त है, क्या उनके लिए आपने कोई ऐसी आचार संहिता निर्धारित की है, यदि की है तो आप हुबली धारवाड़ में कब विमान भेजेंगे, यह बताने की कृपा करें। (**व्यवधान**)

उपसभापति. आपने भूमिका बांध दी है। I am interested in grounding them

श्री गुलाम नबी आजाद: हुबली धारवाड़ एयरपोर्ट दुल्हन की तरह सज गया है, मैंने उसके लिए बहुत अच्छा दुल्हा भी चुन लिया है। एन.ई.पी.सी. प्राइवेट एयरलाइन को साऊथ का पूरा एरिया कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और हैदराबाद को दिया है। पहला जहाज वहां आ रहा है जिसके उद्घाटन के लिए मैं खुद 22 तारीख को वहां जा रहा हूं। दूसरा जहाज बेलगांव, धारवाड़ और कई एरियाज़ को भी कवर कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक महीने तक जब दूसरा जहाज आएगा तो उसमें वह एरिया भी कवर हो जाएगा।

SHRI SOMAPPA R BOMMAI Madam, . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have taken more than half-an-hour on this question

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI Madam, please .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bommai, I am not allowing. I am not allowing. Please take your seat.

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: Madam, Mrs. Margaret Alva

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing it.

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: Day-before yesterday, when she visited Dharwar, she made a statement that within one month, she would see that an Airbus service was started. It is a most beautiful airport. She also challenged that the Members of Parliament from that area were not competent to get an air service to that place. She challenged us. I would like to know from the hon. Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have not allowed this question. We have had so many supplementaries on it. We have to take up other questions. Otherwise, we will have only this question. Question No. 263, please.

Price of Sulphadiazine

*263. DR. NARREDDY THULASI REDDY:

SHRI RAJNI RANJAN SAHU

Will the Minister of CHEMICAL AND FERTILIZERS be pleased to state

(a) what was the price of Sulphadiazine on which formulation prices were based during 1990-91 and 1991-92;

(b) when was the price of the locally produced drug fixed at Rs. 512 per kg. and when were the formulation prices based on this price plus 8 per cent incidentals allowed;

(c) when were the formulation prices based on the landed cost of import fixed and what is the present position;

(d) what is the present landed cost of import of this drug; and

*The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajni Ranjan Saha

(e) what are the bulk drugs production of which has been discontinued by M/s. Rhone Poulanc?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No price revision for single ingredient formulations based on Sulphadiazine was made in 1990-91 and 1991-92. However, prices of combination formulations were revised on the basis of notified prices of Rs. 461/- per kg. during 1990-91 and Rs. 607/- per kg. during 1991-92.

(b) to (d) Price of Rs. 512/- was not notified for indigenously produced bulk drug. However, price of Rs. 511.79 per kg. as the weighted average landed cost was adopted from 6-7-1993 for formulations based on the Sulphadiazine bulk drug. This was revised to Rs. 535.00 per kg. from 24-12-1993 on the basis of the later available data.

(e) To the extent information is available M/s. Rhone Poulenc have discontinued the production of Sulphadimidine, Sulphadiazine. Phathalyl Sulphathiazole, Succinyl Sulphathiazole, Metronidazole and Prochlorperazine bulk drugs.

श्री रजनी रंजन साहू : उपसभापति महोदया, रसायन और उर्वरक मंत्री जनता से उभर कर आए हैं और आम लोगों से इनका लगाव रहा है। यह प्रश्न भी आम लोगों से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आम लोगों को मल्टीनेशलज़ लूटते हैं, उसका इस प्रश्न में एक नमूना है। मैंने पूछा है कि सल्फाडाईज़ीन से बनी फिनिश्ड मेडिसन की कीमत को कैसे निर्धारित किया जाता है और उसे बनाने वाली कौन कौन सी कम्पनियां हैं **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, order in the House.

श्री रजनी रंजन साहू : बल्क ड्रग्ज़ बनाने वाले... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, please, in the House. If anybody wants to talk, he can go to the lobby.

श्री रजनी रंजन साहू : सल्फाडाई ज़ीन भी है या नहीं। पहले पार्ट का उत्तर तो स्पष्ट है, सही दिया है। दूसरे पार्ट का उत्तर अस्पष्ट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रौन प्यूलंक जो पहले मे एंड बेकर के नाम से काम कर रही थी इन्हें सरकार ने हायर इक्विटी, फारेन इक्विटी 74 परसेंट ले कर लगाने की इजाजत दी थी। इनको इस शर्त पर इजाजत दी गई थी कि यह सल्फाडाईज़ीन और दूसरी दवाइयां भी बैसिक स्टेज से हिन्दुस्तान में बनाएंगे और इसके लिए रा-मेटिरियल इम्पोर्ट करने की इजाजत नहीं दी गई थी। अपने देश में बनाने की इजाजत ही दी गई थी। परन्तु इन्होंने कानून का उल्लंघन किया और बेसिक स्टेज से न बना कर, अपने देश से न बना कर यह विदेश से अपने प्रिंसिपल से और अनएस्सोसियेट कम्पनी से इम्पोर्ट करते रहे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने रोने पोलंक को इंटरमीडियेट और बल्क ड्रग इम्पोर्ट करने की इजाजत दी अगर दी तो उन्होंने कभी इस बात की जांच की कि इंडिजेनस रा मैटीरियल और इम्पोरटेड रा मैटीरियल्स..

उपसभापति : छोटा कर दीजिए अदरवाइज जवाब नहीं आयेगा।

श्री रजनी रंजन साहू : मेरा सीधा सवाल है कि उसको रा मैटीरियल इम्पोर्ट करने की इजाजत दी या नहीं दी ?

उपसभापति : मैं समझ गयी, वे भी समझ गये हैं।

श्री रजनी रंजन साहू : और कभी उसकी मानीटरिंग की या नहीं की मेरा यह प्रश्न है।

श्री राम लखन सिंह यादव : यह बात सही है कि दवाई का व्यवहार

रोग के रूप में तो मेरे जैसे लोग करते हैं जो साधारण लोग हैं लेकिन उसका व्यापार तो मेरे ख्याल से दूसरी श्रेणी के लोग, जो हमारे माननीय सदस्य जैसे हैं वैसे लोग करते हैं। तो दोनों में थोड़ा मतभेद होता है। जहां तक इस कम्पनी का सवाल है यह कम्पनी पहले चलती थी लेकिन 1990-91 से यह बंद हो गयी है। कारण उसका है कि जो दवाई बनती थी इनके मारफत वह अपने देश में हम बनाने लगे। काफी बनती है। उनको घाटा लगा था। उसके चलते यह कम्पनी स्वयं बंद हो गयी। इसलिए आगे का प्रश्न अब नहीं उठता।

श्री रजनी रंजन साहू : पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं मंत्री महोदय को जो हमारे बड़े पुराने परिचित हैं, जानते हैं लेकिन इनको मालूम नहीं है कि हमारा इस व्यापार से कोई संबंध नहीं है।

श्री राम लखन सिंह यादव : मैंने यह नहीं कहा कि व्यापार से आपका संबंध है..(व्यवधान) आपकी समझदारी से संबंध है।

श्री रजनी रंजन साहू : दवा से इनको भी संबंध है, हमको भी संबंध है, आप लोगों को भी संबंध है। मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट इम्पोर्ट करने के बाद जिससे इस कम्पनी को, अनइन्टेन्डेड प्राफिट कहते हैं वह, हुआ और जो पैसा इन्होंने कंज्यूमर्स से ज्यादा चार्ज किया, क्या सरकार ने कभी इसका लेखा जोखा लिया है या नहीं लिया? आज ही अखबार में आया है, इकनामिक टाइम्स में, माननीय मंत्री जी उसे पढ़ लेंगे कि सात साल के बाद पी.ए.सी. ने, बी. आई. सी. पी. ने रिपोर्ट दी है कि 4300 रुपया जो कम्पनी दाम चार्ज कर रही थी वह अब 1800 रुपये फिक्स किया गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कंज्यूमर को जो ज्यादा पैसे देने पड़े हैं, 1980 के बाद से आज तक उनको वसूल करने के लिए जो कम्पनी मौजूद है उस पर कार्यवाही करेंगे?

श्री राम लखन सिंह यादव : पेपर में क्या निकला है उस पर तो अभी मैं जवाब नहीं दे सकता हूं लेकिन अगर कभी कम्पनी ने—बंद हो गयी हो तो भी, चलती हो तो भी—कानन से अलग जाकर, कानून को ताक पर रखकर कोई काम किया हो और कानन के जरिये इस तरह से कार्य कर सकते हैं, वसूली कर सकते हैं तो उस पर हम विचार करेंगे।

उपसभापति : नही, लेकिन यह तो सवाल था ओरिजिनल। यह सप्लीमेंट्री नहीं था मंत्री जी। यह ओरिजिनल सवाल में है कम्पनी के बारे में कि उस कम्पनी को आपने इजाजत दी थी यहां बनाने की उन्होंने वह ड्रग नहीं बनाई और उसका बेनीफिट लिया। उसमें आपको क्या जानकारी है वह जवाब दीजिए।

श्री राम लखन सिंह यादव : अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है 1954 में इस कम्पनी ने यहां बनाना शुरु किया। 1991-92 में वह बंद हो गयी और इस बीच में उसने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। लेकिन माननीय सदस्य की नजर में कोई गैर कानूनी काम हुआ हो अभी भी, हमको दें तो उस पर हम विचार करेंगे।

उपसभापति : उन्होने बताया है।

श्री रजनी रंजन साहू : मंत्री जी इग्नोरेंट हैं। उनको जानकारी लेनी चाहिए। उसने इम्पोर्ट किया है।

श्री राम लखन सिंह यादव : उन्होंने इम्पोर्ट किया हो या एक्सपोर्ट किया हो सब कानून के अंदर है तो सही है, गैर कानूनी है तो गैर काननी है।

उपसभापति : मंत्री जी आप सवाल नहीं समझे। सवाल यह है कि इस कम्पनी को इजाजत इसलिए दी गयी थी कि वह ड्रग यहां बनाये हिंदुस्तान में। उस कम्पनी ने यहां ड्रग न बनाकर इम्पोर्ट कर हाई प्राइसिग की। यह सवाल है उनका। इससे पहले तो हो चुका है। आप बताइये। (**व्यवधान**)

श्री राम लखन सिंह यादव : अभी जो हमारे यहां पर है, जो दाम इसमें लगता है उससे सस्ते में हमको मिल रहा है इसलिए आज यह प्रश्न नहीं उठता है।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Madam, the drugs marketed by various pharmaceutical companies, containing sulphadiazine, metrodezanol and chloroflurozine are being sold at the rate of Rs. 1,600—1,700 when calculated in value per kilo. What steps does the Government propose to take to reduce the gap between the bulk prices and retail prices of these drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): Madam, this information is not correct. There was some complaint of dumping also. The price of the imported material that comes into the country is often, in this case, lower than the international price—of Hong Kong, for instance... (*Interruptions*)...

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: You are misleading the House. There is a wide gap between retail prices and bulk prices.

SHRI EDUARDO FALEIRO: The position is as follows: As far as the bulk drug is concerned, now it is not being manufactured in the country—it is being imported. The prices are lower in the country—and that is the complaint—than the international prices. For instance, in Hong Kong or the domestic price in the U.S.A. ...(*Interruptions*).. As far as the formulae are concerned, there is a mathematical formula and that is to be applied. If you have any particular instance, you please bring it to us, and I will look into the matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Foreign collaboration for Car manufacturing

*264. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE:

SHRI V. NARAYANASAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many car manufacturing units in India have applied for licence for collaboration with foreign car manufacturing units; and

(b) what is the total investment which Government propose to get in India by allowing the joint venture car manufacturing units to be set up in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) After the New Industrial Policy, 1991, three car manufacturing units have applied for and been granted foreign collaboration approval.

(b) In the case of Hindustan Motors, the foreign equity participation would be 50 per cent amounting to Rupees 60 crores. In the case of Premier Automobiles, the foreign equity participation would be upto 50 per cent amounting to between Rs. 60 crores and Rs. 120 crores. The Maruti Udyog Ltd. is already a Joint venture and the foreign equity in this company has been increased from 40 per cent to 50 per cent.